

सतना

18 अगस्त 2024
रविवार

दैनिक मीडिया ऑडिटर



पेरिस ओलंपिक 2024...

@ पेज 7

लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियोएक्टिव हो गया लीक, 2 कर्मचारी बेहोश



- 1.5 किमी का एरिया खाली कराया, टर्मिनल-3 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सौंपा

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ के चौथी चरण सिंह (अमौसी) एयरपोर्ट पर रेडियोएक्टिव लीक हुआ। इससे 2 कर्मचारी बेहोश हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने टर्मिनल-3 पर सर्व ऑपरेशन शुरू किया। 1.5 किमी का पर्याय खाली कराया। एहतियात के तौर पर लोगों की एंट्री बंद कर दी। 1 घंटे तक जांच-पड़ताल की गई। अब स्थिति सामान्य है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट और प्रायरिंग प्रायरिंग नहीं है। फ्लाइट लखनऊ से गुवाहाटी जाती है। उसी दौरान एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर स्कैनिंग के दौरान मशीन से बोप की आवाज आने लगी।

रहस्य बन रहा कोलकाता का डॉक्टर रेप मर्डर केस!

- हमला करने कहां से आए थे 7000 गुड़े, नहीं चल पाया पता
- आरोपियों की लिस्ट में कैब ड्राइवर, डिलीवरी बॉय का भी नाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 8 अगस्त की रात जो कुछ हुआ, वो बेहद सर्वानक है। एक जनियर डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म हुआ और इसके बाद गला छोटकर उत्की हल्ता कर दी गई। इस घटना के विरोध देशभर के डॉक्टर सड़कों पर हैं लेकिन, इससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना, 14 अगस्त की रात उस वक्त हुई, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन



कर रहे थे। विरोध जता रहे इन डॉक्टरों पर एक भी ने हमला किया। वे भीड़ मामूली नहीं थी। इस भीड़ में करीब सात हजार लोग शामिल थे।

अब सचाल ये है कि डॉक्टरों पर हमला करने के लिए आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये गुड़े कहां से आए थे। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस की तात्परी में ऐसे कई सचाल हैं, जो अभी तक रहस्य बोर्ड हैं। वहाँ, इस मामले में कोलकाता पुलिस ने लिस्ट बनाई है, उनके नाम भी चौकाने वाले हैं। पुलिस की इस लिस्ट में एक महिला संघर्ष टेंप्स लोगों के नाम हैं। पुलिस ने कई युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें ऐप-कैब ड्राइवर, डुकानदार, फूड डिलीवरी बॉय और कई बेरोजगार युवा शामिल हैं।

हमने जी20 को एक नया ढंग देने का संकल्प लिया



पीएम बोले- हमने विकास से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की

मोदी ने कहा-दुनिया की चुनौतियों से निपटने में भारत बना बड़ा पॉवर

मुद्दों पर अपने द्विक्षेपण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है। शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने कहा, 2022 में जब भारत ने जी20 की अध्यक्षता संभाली, तो हमने जी20 को एक नया ढंग देने का संकल्प लिया। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच बन गया, जहां हमने विकास से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा की, और भारत ने ग्लोबल साउथ की मैजिस्ट्री कर रखा है, जिसमें वैश्वक दृष्टिकोण के देशों का एक मंच पर विभिन्न किया। पीएम ने कहा, हमने समावेशी और विकासोन्मुखी द्विक्षेपण के साथ जी20 को आगे बढ़ाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वह ऐतिहासिक क्षण था जब अकेली संघ को जी20 की स्थायी सदस्यता मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष और अन्वयन के बीच मौजूदा वैश्वक परिदृश्य में अनिश्चितता के तहत प्रकाश डाला और कहा कि वैश्वक शासन और वित्तीय संस्थान आज की चुनौतियों से निपटने में अक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हम ऐसे समय में मिल गये हैं कि नवंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। मिशन की दूसरी पालाइट में अधिकारियों को आधार पर जी20 एंड-बैठ तैयार हो रहे हैं, जब परी दुनिया में अनिश्चितता का प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है।

कर्नाटक सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में चलेगा केस

राज्यपाल ने मंजूरी दी

- सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप



बंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जूँझ भ्रष्टाचार मामले में केस लगाया गया। राज्यपाल थावरद गहलोत ने शनिवार को इसकी अधिकारिक जमीन के मालिक घोषित कर दी है। सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जूँझ भ्रष्टाचार मामले के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाया गया। नोटिस जारी कर प्राधिकरण से 7 दिन में जावा मार्ग था। 1 अप्रैल को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवेदनिक शक्तियों के दुर्लक्षण को आरोप लगाया। प्राधिकरण घोषणे में मूख्यमंत्री अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। परिवर्तित टीजे अब्राहम, प्रदीप और सेहमी साइट्स को बोखार्डी से राखिल करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलकर महीनी साइट्स को बोखार्डी से राखिल गया। 1992 में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथारिटी ने कुछ जमीन रिहायरी इलाके में विकासित करने के लिए फर्जी साइट्स को ली थी। इनके बदले प्राधिकरण की इंसेटिव 50-50 स्कीम के तहत जिनकी भूमि अधिग्रहित होती है उन्हें विकासित भूमि में 50 फीसदी साइट्स एक वैकल्पिक साइट दी गई। 1992 में प्राधिकरण ने इस जमीन को डीनोटाइक एक कृषि भूमि से अलग किया।

इन दिनों चौतरफा हमलों में घिर रहे हैं राहुल गांधी

देश विरोधियों से मिलीभगत विदेश की नागरिकता के लग रहे आरोप



राजेश सिंह नए रक्षा सचिव, पुण्य सलिला स्वारथ्य सचिव बनीं

- केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कर्मी ने 15 अफसरों के विभाग बदले

नई दिल्ली (एजेंसी)। सीनियर एजिएप्स अफसरों को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी उड़े चौतरफा घटने की तैयारी कर रही है। वहाँ अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनराज ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति सुरीम कर्ट से चाहते हैं कि वो भारत विरोधी नैटवर्क को हवा दें। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी स्वरात्रि विवादों के बीच स्वारथ्य पर आरोपण की दिशा नाम दिया। विवाद भारत के लिए एक बड़ा घटना है। वहाँ अब विवाद के तहत सचिव राज्यपाल के लिए कर्मी ने 15 अफसरों के विभाग बदले।

नई दिल्ली (एजेंसी)। सीनियर एजिएप्स अफसरों की नई सचिवता को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी उड़े चौतरफा घटने की तैयारी कर रही है। वहाँ अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनराज ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति सुरीम कर्ट से चाहते हैं कि वो भारत विरोधी नैटवर्क को हवा दें। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी स्वरात्रि विवादों के बीच स्वारथ्य पर आरोपण की दिशा नाम दिया। विवाद भारत के लिए एक बड़ा घटना है। वहाँ अब विवाद के तहत सचिव राज्यपाल के लिए कर्मी ने 15 अफसरों के विभाग बदले।

भागलपुर में अगवानी पुल का सुपर स्ट्रक्चर फिर गिरा

3 साल में तीसरा हादसा, बिहार में 2 साल में गिरे छोटे-बड़े 21 पुल



प्रोजेट पूरा होने पर झारखंड से जुड़ जाएगा तार बिहार

ये पुल अगुवानी और सुल्तानगंज घटा (भागलपुर जिला) के बीच बन रहा है जो बर्दानी खण्डिया है। 31 अप्रैल 1992 में किलोमीटर इलाके में कुछ जमीन रिहायरी इलाके में गिरे हैं। उन्हें बदले प्राधिकरण की इंसेटिव 50-50 स्कीम के तहत जिनकी भूमि अधिग्रहित होती है उन्हें विकासित भूमि में 50 फीसदी साइट दी गई। 1992 में प्राधिकरण ने इस जमीन को डीनोटाइक कर कृषि भूमि से अलग किया।

जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर के अंदर होगी लाइव स्ट्रीमिंग



बांके बिहारी मंदिर के अंदर होगी लाइव स्ट्रीमिंग।

ही सीमित रखने का आदेश दिया है। कोटे ने सरकार की शेष योजना को जारी रखने की अनुमति दी है। कोटे ने रिसोर्सों के तहत स्विल जज जूनियर डिलीजन यारों के प्रयोग से सीसीटीवी के क्षेत्रों में विकास करने की योजना दी है। हाइकोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह स्विल जज के निर्देश का अनुपालन कराएं। 1939 के मुरियक के आदेश से भीड़ प्रबंधन, मंदिर प्रबंधन व चौपाल के द्वारा दिया गया था। वहाँकि इसे

विषार

यूएस से मिले आधुनिक हथियारों को लेकर यूक्रेन
तो रूसिया के भीतर घुसता ही चला जा रहा है

रूस-यूक्रेन युद्ध के तीसरे वर्ष में युद्ध मैदान के हालात में आये बड़े परिवर्तन ने सबको चौंका दिया है। जिस तरह यूक्रेन रूस को उसके घर में घुसकर मार रहा है उससे समूची दुनिया हैरान रह गयी है। हालांकि यहां एक सवाल यह उठ रहा है कि यूक्रेन अमेरिकी हथियारों के साथ जिस तरह रूस में हमले कर रहा है क्या उससे अमेरिका की हथियार नीति का उल्लंघन नहीं हो रहा है? हम आपको बता दें कि यूक्रेन ने कहा है कि उसके सैनिक 6 अगस्त को घुसपैठ शुरू करने के बाद से अब तक रूस में 35 किमी (21 मील) तक घुस आए हैं। कीव का कहना है कि उसे रूसी भूमि पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को रूस से बचाने के लिए एक बफर जोन बना रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका का कहना है कि अगर यूक्रेन अमेरिकी हथियारों और वाहनों का उपयोग करके गांवों और अन्य गैर-सैन्य ठिकानों पर कब्जा करना शुरू कर देता है, तो इससे अमेरिकी हथियार नीति पर सवाल उठ सकते हैं। अमेरिका को यह भी चिंता है कि युद्ध में अमेरिका और नाटो देशों के हथियारों का रूस के खिलाफ खुलकर विरोध होने से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि वाशिंगटन की हथियार नीति यूक्रेन द्वारा रूस पर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाई गई थी। अमेरिका का कहना है कि राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने हमले के समर्थन या विरोध में कोई मजबूत सार्वजनिक रुख नहीं अपनाया है। वैसे अभी यह स्पष्ट नहीं है कि रूस में यूक्रेनी घुसपैठ में कौन से अमेरिका निर्मित हथियार या उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। हम आपको बता दें कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने के बाद से अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और उसे 50 बिलियन डॉलर से अधिक के सैन्य उपकरण प्रदान किए हैं। हालांकि अपने भराजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रूस के साथ व्यापक संघर्ष से बचने की कोशिश करते हुए, बाइडन प्रशासन ने शुरू में अपने हथियारों के उपयोग पर सख्त शर्तें लगा दीं थीं। लेकिन अब उन शर्तों को धीरे-धीरे ढीला कर दिया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदमीर जेलेंस्की की अपील के बावजूद अमेरिका अभी भी रूसी क्षेत्र पर लंबी दूरी के हमलों के लिए अपने हथियारों के उपयोग की अनुमति नहीं दे रहा है। वैसे बाइडन प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से लंबी दूरी को परिभाषित नहीं किया है। विशेषज्ञों का इस बारे में कहना है कि अमेरिका ने धीरे-धीरे यूक्रेन द्वारा अपने हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंधों में ढील दे दी है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप या अमेरिका के खिलाफ आशंका के मुताबिक अब तक कोई हमला नहीं किया है। हम आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने हाल ही में कहा था कि हम बहुत स्पष्ट और सुसंगत रहे हैं कि हम वास्तव में यूक्रेन को अपनी सीमाओं के अंदर आक्रामकता के खिलाफ खुद का बचाव करने पर ध्यान केंद्रित करते देखना चाहते हैं।

**तानाशाह नहीं हैं प्रधानमंत्री मोदी ! आलोचकों
की परवाह न कर अपनी राह चलते हैं**

प्रो. संजय द्विवेदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कुछ तो खास है कि वे अपने विरोधियों के निशाने पर ही रहते हैं। इसका खास कारण है कि वे अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट हैं और लीपापोती, समझौते की राजनीति उन्हें नहीं आती। राष्ट्रहित में वे किसी के साथ भी चल सकते हैं, समन्वय बना सकते हैं, किंतु विचारधारा से समझौता उन्हें स्वीकार नहीं है। उनकी वैचारिकी भारतबोध, हिंदुत्व के समावेशी विचारों और भारत को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की अवधारणा से प्रेरित है। यह गजब है कि पार्टी के भीतर अपने आलोचकों पर भी उन्होंने कभी अनुशासन की गाज नहीं गिरने दी, यह अलग बात है कि उनके आलोचक राजनेता ऊबकर पार्टी छोड़ चले जाएं। उन्हें विरोधियों को नजरंदाज करने और आलोचनाओं पर ध्यान न देने में महारात हासिल है।

आलोचनाओं पर ध्यान न देने में महारत हासिल है



इसके उलट पार्टी से नाराज होकर गए अनेक लोगों को दल में वापस लाकर उन्हें सम्मान देने के अनेक उदाहरणों से मोदी चकित भी करते हैं। किसी व्यक्ति की लोकतांत्रिकता उसकी अपने दल के साथियों से किए जा रहे व्यवहार से आंकी जाती है। मोदी यहां चाँकाते हुए नजर आते हैं। वे दल के सर्वोच्च नेता हैं किंतु उनका व्यवहार 'आलाकमान' सरीखा नहीं है। आप उन्हें तानाशाह भले कहें, किंतु तटस्थ विश्लेषण से पता चलता है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आजतक उनकी आलोचना करने वाले अपने किसी साथी के विरुद्ध उन्होंने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होने दी। कल्पना करें कि किसी अन्य दल में अपने आलाकमान या सर्वोच्च नेता की आलोचना करने वाला व्यक्ति कितनी देर तक अपनी पार्टी में रह सकता है। नरेंद्र मोदी यहां भी रिकार्ड बनाते हैं। जबकि भाजपा में अनुशासन को लेकर कड़ी कार्रवाईयां होती रही हैं। भाजपा और जनसंघ के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे बलराज मधोक से लेकर कल्याण सिंह, उमा भारती, बाबूलाल मरांडी, बीएस येदुरप्पा जैसे दिग्गजों पर कार्रवाईयां हुई हैं, तो गोविंदाचार्य पर भी एक कथित बयान को लेकर गाज गिरा। उन्हें अध्ययन अवकाश पर भेजा गया, जहां से आजतक उनकी वापसी नहीं हो सकी है। मोदी का ट्रैक अलग है। वे आलोचनाओं से घबराते नहीं और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की छूट देते हुए अपने आलोचकों को भरपूर अवसर देते हैं। यह कहा जा सकता है कि मोदी

आलोचनाओं के केंद्र में रहे हैं, इसलिए इसकी बहुत परवाह नहीं करते हैं। वे कहते भी रहे हैं कि उनके निंदक जो पत्थर उनकी ओर फेंकते हैं, उससे वे अपने लिए सीढ़ियां तैयार कर लेते हैं। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी के भीतर भी उनके आलोचकों और निंदकों की पूरी फौज सामने आती है, जो तमाम मुद्दों पर उन्हें घेरती रही है। आश्वर्यजनक रूप से मोदी उनके विरुद्ध पार्टी के अनुशासन तोड़ने जैसी कार्यवाही भी नहीं होने देते हैं। इसमें पहला नाम गांधी परिवार से आनंद वाले वरुण गांधी का है, जिन्हें भाजपा ने सत्ता में आने के बावजूद संगठन में महासचिव का पद दिया। वे सांसद भी चुने गए किंतु पार्टी संगठन में उनकी निष्क्रियता से महासचिव का पद छला गया और वे मोदी के मुखर आलोचक हो गए। अपने बयानों और लेखों से मोदी को घेरते रहे। बावजूद इसके निष्क्रियता से महासचिव का पद छला गया और वे पार्टी के सदस्य हैं। खुलेआम आलोचनाओं और अखबारों में लेखन के बाद भी उन्हें आज तक एक नोटिस तक पार्टी ने नहीं दिया है। हां, इस बार वे टिकट से जरूर बंचित हो गए। उनकी जगह कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद के पीलीभीत से लोकसभा का टिकट मिल गया। जितन जीत भी गए। दूसरा उदाहरण फिल्म अभिनेता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे शारुद्ध सिन्हा का है। सिन्हा मोदी के मुखर आलोचक रहे और समय-समय पर सरकार पर इट्पणी करते रहे। अंततः वे भाजपा छोड़कर पहले कांग्रेस

भारत के लिए क्यों जरूरी है सेक्युलर सिविल कोड? अलग-अलग पर्सनल लॉ के चलते क्या हो रही हैं परेशानियां?

अश्विनी उपाध्याय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता (एससीसी) की जोरदार बकालत करते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और इसके बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया तथा इस विषय पर देश में गंभीर चर्चा की जरूरत पर बल दिया। इसके बाद से देश में सेक्युलर सिविल कोड के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गयी है। जहां विपक्ष कह रहा है कि ना तो भाजपा सेक्युलर है और ना ही सिविल है वर्हं सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का स्वागत किया जाना चाहिए और इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान यही कहता है कि सभी देशवासियों के लिए एक ही नागरिक संहिता होनी चाहिए। आइए वहले समझते हैं कि देश में अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू होने से क्या परेशानियाँ हैं फिर समझेंगे कि क्यों भारत के लिए जरूरी समान नागरिक संहिता।

१. मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहु-विवाह करने की छूट है जिसके अन्य धर्मों में एक पति-एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। बांझपन या नपुंसकता जैसा उचित और व्यावहारिक कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई, पारसी के लिए दूसरा विवाह करना एक गंभीर अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा ५९४ में बहुविवाह के लिए ७ वर्ष की सजा का प्रावधान है दूसीलिए कई लोग दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। भारत जैसे सेक्युलर देश में मौज मस्ती के लिए भी चार निकाह जायज है जबकि इस्लामिक देश पाकिस्तान में बहली बीवी की इजाजत के बिना शौहर दूसरा निकाह नहीं कर सकता है। मानव इतिहास में %एक पति- एक पत्नी% का नियम पर्वप्रथम भगवान श्रीराम ने लागू किया था और यह किसी भी प्रकार से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं बल्कि सिविल राइट,



ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी और राइट टू डिग्निटी का मामला है इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल और रिलिजन न्यूट्रल होना चाहिए।

2. कहने को तो भारत में संविधान अर्थात् समान विधान है लेकिन विवाह की न्यूनतम उम्र भी सबके लिए समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है और माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह योग्य मान लिया जाता है इसलिए 9 वर्ष की उम्र में लड़कियों का निकाह कर दिया जाता है जबकि अन्य धर्मों में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18

वर्ष और लड़कों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार कह चुका कि 20 वर्ष से पहले लड़कों शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती है और 20 वर्ष से पहले गर्भधारण करना जच्चा-बच्चा दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लड़का हो या लड़की, 21 वर्ष से पहले दोनों ही मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, 21 वर्ष से पहले तो बच्चे ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाते हैं और आर्थिक रूप से माता-पिता पर निर्भर होते हैं इसलिए विवाह की न्यूनतम उम्र सबके लिए एक समान 21 वर्ष करना नितांत

आवश्यक है। %विवाह की न्यूनतम उम्र% किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है बल्कि सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी और राइट टू हेल्थ का मामला है इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल रिलिजन न्यूट्रल और 21 वर्ष होना चाहिए।

3. तीन तलाक अवैध घोषित होने के बावजूद अन्य प्रकार के मौखिक तलाक (तलाक-ए-हसन एवं तलाक-ए-अहसन) आज भी मान्य हैं और इसमें भी तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है और केवल 3 महीने तक प्रतीक्षा करना है जबकि अन्य धर्मों में केवल न्यायालय के माध्यम से ही विवाह-विच्छेद हो सकता है। हिंदू, ईसाई, पारसी दंपति आपसी सहमति से भी मौखिक विवाह-विच्छेद की सुविधा से वंचित हैं, मुसलमानों में प्रचलित मौखिक तलाक का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होने के कारण मुस्लिम बेटियों और उनके माता-पिता भाई-बहन और बच्चों को हमेशा भय के बातावरण में रहना पड़ता है। तुर्की जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में भी अब किसी तरह का मौखिक तलाक मान्य नहीं है इसलिए तलाक लेने का तरीका जेंडर न्यूट्रल रिलिजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफार्म होना चाहिए।

4. मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत एवं दान मान्य है लेकिन अन्य धर्मों में केवल पंजीकृत वसीयत एवं दान ही मान्य है। मुस्लिम कानून में एक-तिहाई से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता है जबकि अन्य धर्मों में शत-प्रतिशत संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। वसीयत और दान किसी भी तरह से धार्मिक या मजहबी विषय नहीं है बल्कि सिविल राइट, ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी और राइट टू लिबर्टी का मामला है इसलिए यह जेंडर न्यूट्रल रिलिजन न्यूट्रल और सबके लिए यूनिफार्म होना चाहिए।

कर्नाटक सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा

बैंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जनीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार (17 अगस्त) को इसकी अधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया पर मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को राजकारन ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की ओर और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। एमपीयूई घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्षिविस्ट टी. जे. अबासाम, प्रदीप और सेहवायी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने एमपीयूई अधिकारियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए।

हिमाचल में फिर बादल फटा, नेशनल हाईवे बंद

नई दिल्ली (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। इससे तकलीफ-नोगली में 30 मीटर तक की रोड बह गई। मंडी में तेज वारिश के चलते चंडीगढ़-मानाली नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तर प्रदेश के कानून में गंगा नदी खतरे के निशान से सिफर 1 मीटर नीचे बह रही है। इससे निशाने इलाकों में पानी भर गया है। करीब 50 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान में भारी बारिश के कारण जैसलमेर में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने शनिवार (17 अगस्त) को 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ उक्सरी के पुलवामा में भी शनिवार को बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज वारिश के कारण यहां बाढ़ जैसे स्थिति बन गई है। कई घरों और निचले इलाकों में पानी भर चुका है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एसीडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू और परेंसन शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई की रात कुल्लू मंडी, शिमला जिलों में बादल फटा था। इसके कारण इन जिलों में 56 से ज्यादा लोग बह गए थे। हादसे में मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। शुक्रवार को 4 शव और बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि 14 लोग अभी भी लापता हैं।

नीतीश ने राजगीर खेल परिसर का किया निरीक्षण

पटना (एजेंसी)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर खेल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्प्रॉट्स एकडी में निर्माणाधीन स्टेडियम का भी जागता लिया निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बते हुए निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस खेल अकादमी में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता-रेटिंग ढंग से कार्यों को पूर्ण करें। यह अकादमी देश के लिए अनोखी और अत्यधिक सुविधाओं से लैस होंगी। यहां कई खेलों के ट्रैनिंग मैटर के अलावा विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय भी होगा। इन प्रयासों से राज्य में खेल का वातावरण तेवर करने में मिलेगी साथ ही प्रतीक्षावान युवाओं को अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजगीर ऐतिहासिक स्थल है। यहां सभी प्रकार की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर्यटक आते हैं। राजगीर अब पर्यटकों के आवाहन को केंद्र बन गया है। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सासंदर्भ कौशलेंद्र कुमार, विधायक कृष्ण मुरारी शरण उपर्युक्त प्रमुखिया, पूर्व विधायक चंद्रसेन कुमार, पूर्व विधायक ईं. सुनील, पूर्व विधायक राजू यादव सहित अन्य जननप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव सह मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रन शंकरन, पटना प्रमंडल के आयुक्त पर्यंक बरबरे, पटना प्रशंसन की पुलिस महानिदेशक गरिमा मलिक, नालंदा के जिलाधिकारी शशोक्त शुभंकर, नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मित्रा साहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।

निर्भया की मां का आरोप-दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में विफल

सीएम ममता घटना से ध्यान भटकाने की कर रही कौशिश

नई दिल्ली। दिल्ली सामूहिक बलाकार मामले की पीड़िता निर्भया की मां ने कोलकाता के अराजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण महिला चिकित्सक के साथ कथित बलाकार और हत्या की घटना को लेकर शनिवार को कड़ा आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि पृथक्क बगाल की मुख्यमंत्री ममता जी को इस्टीफा दे देना चाहिए। निर्भया की मां अपने पद, नाम और आरोप लागाका कि ममता के अवलोकन से दक्षिण दिल्ली के खिलाफ कार्रवाई के बाजार मुद्रे।



से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जब तक केंद्र और राज्य सरकारें हैवानियत करने वालों को अवलोकन से तकाल सजा दिलाने को लेकर गंभीर नहीं होंगी, तब तक आए देश के दुरुपयोग कर धनांश के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाजार मुद्रे।

ग्लोबल साउथ के देशों को एक-दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' विभाग से जुड़े मुद्रों पर चर्चा करने का एक मंच बन गया है। उन्होंने नई दिल्ली की मेजबानी में दिजिटल रूप से आयोजित ग्लोबल साउथ सम्मेलन में कहा कि 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' सम्मेलन एक ऐसा मंच है, जहां हम उन लोगों की जरूरतों, आकांक्षाओं को आवाज देते हैं, जिन्हें अभी तक अनुसुना किया गया है। 'ग्लोबल साउथ' शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर अधिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो विकासनी-प्रयोग से जुड़े हो आगे बढ़ावा देना चाहता है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के समें आ रही चुनौतियों पर कहा, "अनिश्चितताओं का माहात्मा है, हम भोजन, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा की समस्याओं का समान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद, उत्तराधीन अलगावाद, हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं।"



ग्लोबल साउथ के देशों को एक-दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए: प्रधानमंत्री

स्वीडन अपने ही नागरिकों को देश छोड़ने के पैसे देगा, बड़ों को 80 और बच्चों को 40 हजार मिलेंगे

स्वीडन (एजेंसी)। स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है। स्वीडन की इमोग्रेशन मिनिस्टर मारिया माल्मर स्टेनगार्ड ने ये प्रस्ताव पेश किया है। स्टेनगार्ड ने कहा कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है वह फिर वे लोग जो यहां भुलम्बल नहीं पाए हैं वे स्वीडन छोड़ सकते हैं।

यूरोपीय वेबसाइट देश से आरोप लगाया। एमपीयूई घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्षिविस्ट टी. जे. अबासाम, प्रदीप और सेहवायी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने एमपीयूई अधिकारियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए।



स्वीडन लोगों को पसंद नहीं करता। हेरानी की बात ये है कि स्वीडन में ये प्रस्ताव तब पाया जाता है कि जब देश छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। स्वीडिंग माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक यदि कोई लोग अपने बड़े बालों के साथ बाहर जाता है तो उसे 10 हजार रुपए मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें किए गए ये नियम लागू होता था, लेकिन वारे नागरिकों पर भी ये नियम लागू होता था, लेकिन वारे नागरिकों पर भी ये नियम लागू होता था।

प्रवासियों को बाहर छोड़ने की आवादी बड़ी, मूल आवादी देश छोड़ने वाले लोगों की आवादी बड़ी है। स्वीडन के नव्वे बाहर छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। स्वीडिंग माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2024 में स्वीडन में आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। 150 सालों

रहे हैं। वर्दी, प्रवासियों के लिए स्वीडन पसंदीदा जगह बना हुआ है। स्वीडन में प्रवासियों की संख्या भी ज्यादा हो गई है, जो स्वीडन की कूल आवादी की पांचवां हरिस्स है। प्रवासियों को बढ़ती आवादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई पांचवां घर बनाया है। स्वीडन में सीरिया, सोमालिया, ईरान और इराक से आए लोगों की आवादी काफी ज्यादा है।

देश में हिंसक घटनाएं बढ़नी वाली घटनाएं वर्दी, प्रवासियों पर लाग रहे आरोप; हाल के कुछ सालों में स्वीडन में हिंसा की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। पुलिस के आकड़ों के अनुसार पिछले साल स्वीडन में कम से कम 348 गोलीबारी की घटनाएं हुईं। इनमें कम से कम 52 लोग मरे गए। हिंसा की इन घटनाओं को प्रवासियों की बढ़ती आवादी से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वीडन में नव्वे के दशक से बड़ी संख्या में प्रवासियों को शरण देता आ रहा है तेकिन अक्टूबर 2022 में उल्फ़ क्रिस्टरसन के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश की नीति में बदलाव आया है। दरअसल उनकी सरकार

बीसीसीआई ने ठुकराया आईसीसी का प्रस्ताव

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से दिए गए महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आईसीसी की मेजबानी पर अंतर्मत फैसला 20 अगस्त को लेना है। बता दें कि, इस साल बांगलादेश में 3 और 20 अक्टूबर के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। लेकिन, बांगलादेश में हालात अस्थिर हैं।

बता दें कि, ऐश्वर्य हसीना की सरकार गिरने के बाद बांगलादेश में अराजक स्थिति है। ऐसे में भारत को मेजबानी का आंपर दिया गया था। अब भारत को पैसों हटने के बाद श्रीलंका और यूरोप दूसरे विकल्प बचे हैं। श्रीलंका में अक्टूबर में बारिश होती है।

रिकू सिंह- संजू सेमसन को नहीं मिला मौका, देखें घरेलू क्रिकेट में आंकड़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। दलीप ट्रॉफी 2024 अब नए फॉर्मेट में नज़र आएगी। जोनल फॉर्मेट में इसका आयोजन नहीं होगा बल्कि, बीसीसीआई की चयन समिति ने अवधिकार में देखा जाना है। मैं बीसीसीआई की घोषणा की। 4 टीमों में 61 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये चुने गए नाम काफी अहम हैं। दलीप ट्रॉफी भारतीय टेस्ट टीम के चयन का बोर्ड होगा। ऐसे में इन 61 नामों में से ही खिलाड़ियों का चयन होगा। वहाँ इन 4 टीमों में दो खिलाड़ियों रिकू सिंह और संजू सेमसन का चयन होगा। वहाँ इन 4 टीमों में दो खिलाड़ियों को चयन की जाएं गए हैं। अब तक भारत के लिए एक टेस्ट नहीं खेल पाए हैं, दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के बाद चृष्णुमान साहा और ऋषभ पंत को तरजीह मिली, लेकिन इस दौरान संजू पर एक बार भी भरोसा नहीं जाता गया। वह फरवरी 2024 में

रणजी ट्रॉफी में आखिरी बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे।

अंतर्मत के खिलाफ उत्तर प्रदेश की टीम 198 रन बनाए थे। जबकि इस दौरान रिकू ने 26 रन ठोके थे। जनरी 2024 में कर्कल के खिलाफ भी रिकू ने बेहरीन 92 रन की पारी केली थी।

2018-19 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने कई मौकों पर उत्तर प्रदेश की टीम दिलाई और 105.88 की ओसत से 953 रन बनाए। वहाँ संजू के आंकड़ों की बात करें तो वह 2011 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तक भारत के लिए एक भी टेस्ट नहीं खेल पाए हैं, दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के बाद चृष्णुमान साहा और ऋषभ पंत को तरजीह मिली, लेकिन इस दौरान संजू पर एक बार भी भरोसा नहीं जाता गया। वह फरवरी 2024 में

मार्ना मोर्केल बने टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच, 1 सितंबर से संभालेंगे कमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मार्ना मोर्केल को टीम इंडिया का नया गेंदबाजी कोच बनाया गया है। उनका कॉर्नेल्ट 1 सितंबर से शुरू होगा। जय शाह ने इस बात की जानकारी खुलौ एक क्रिकेट बेसिस्ट को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे। सचिन तेंदुलकर से लेकर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पीरी श्रीजेश तक ने इस मौके पर देश के लोगों को शुभकामनाएं दी। विराट कोहली, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सचिन तेंदुलकर ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक्सिफ खिलाड़ी ही हीं खेलते। हां भारतीय और निष्ठा से अपना काम करता है वह टीम इंडिया के लिए अधिक खिलाड़ी है। इसलिए जब आज राष्ट्रगां बजेगा, तो जान लें कि ये आपके लिए है, और मुझे उम्मीद है कि आज भी वैसा ही महसूस करेंगे जैसा मैं हर बार भारत के लिए खेलने के लिए मैं उत्तर समय इसे सुनकर किया था।

पेरिस ओलंपिक 2024 पदकवीरों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी



नई दिल्ली (एजेंसी)। खेलों के सबसे बड़े महारूप्तं दो मेडल मिले, जिनमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ओलंपिक के लिए भारत का 117 सदस्यीय दल पेरिस गया था। जिसमें से ज्यादातर एथलीट्स स्वदेश लौट आए हैं। वहाँ कई खिलाड़ियों सहित भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अपनी टीम की ओर से पीएम को हॉकी स्टिक भेंट की। इस दौरान पीएम ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित की जाया। हांटाकि, कुछ खिलाड़ी अभी स्वदेश नहीं लौटे हैं। जिनमें जैवलिन थोआं नीरज चोपड़ा जर्मनी में हैं, जहां उनकी सर्जरी होनी है। वहीं रेसलर विनेश फोगाट 17 अगस्त को भारतीय लौटेंगी। बैडमिंटन खिलाड़ी भी इस इंवेंट का खिस्ता नहीं बन गया। पीरी श्रीजेश ने ये बात फैसले के लिए एक्टिविस्ट के खिलाड़ियों ने कहा। निशानेबाज मनु भाकर ने पीएम मोदी को पिस्टल दी, तो रेसलर अमन सहायता और हॉकी टीम ने जर्सी सौंपी। इन जर्सीयों पर

आईसीसी ने अभी तक अपलोड नहीं की टी20 विश्व कप के न्यूयॉर्क मुकाबलों की पिच रेटिंग

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पारंपरिक

आईसीसी की पिच और

आउटफील्ड पर असमान

उड़ान और धोनी आउटफील्ड

की दुनिया भर में आत्मोचना हुई

थी जिसमें 120 से तक के

स्कोर का पीछा करना मुश्किल

हो गया था। यह अभी तक

स्पष्ट नहीं है कि पिच और

आउटफील्ड रेटिंग अभी तक

46 दिन के बाद भी आईसीसी

की वेसाइट पर अपलोड नहीं

हो गई। यह अभी तक

कोई अपडेट नहीं किया गया है।

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पारंपरिक

आईसीसी की पिच और

आउटफील्ड पर असमान

उड़ान और धोनी आउटफील्ड

की दुनिया भर में आत्मोचना हुई

थी जिसमें 120 से तक के

स्कोर का पीछा करना मुश्किल

हो गया था। यह अभी तक

स्पष्ट नहीं है कि पिच और

आउटफील्ड रेटिंग अभी तक

46 दिन के बाद भी आईसीसी

की वेसाइट पर अपलोड नहीं

हो गई। यह अभी तक

कोई अपडेट नहीं किया गया है।

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पारंपरिक

आईसीसी की पिच और

आउटफील्ड पर असमान

उड़ान और धोनी आउटफील्ड

की दुनिया भर में आत्मोचना हुई

थी जिसमें 120 से तक के

स्कोर का पीछा करना मुश्किल

हो गया था। यह अभी तक

स्पष्ट नहीं है कि पिच और

आउटफील्ड रेटिंग अभी तक

46 दिन के बाद भी आईसीसी

की वेसाइट पर अपलोड नहीं

हो गई। यह अभी तक

कोई अपडेट नहीं किया गया है।

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पारंपरिक

आईसीसी की पिच और

आउटफील्ड पर असमान

उड़ान और धोनी आउटफील्ड

की दुनिया भर में आत्मोचना हुई

थी जिसमें 120 से तक के

स्कोर का पीछा करना मुश्किल

हो गया था। यह अभी तक

स्पष्ट नहीं है कि पिच और

आउटफील्ड रेटिंग अभी तक

46 दिन के बाद भी आईसीसी

की वेसाइट पर अपलोड नहीं

हो गई। यह अभी तक

कोई अपडेट नहीं किया गया है।

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पारंपरिक

आईसीसी की पिच और

आउटफील्ड पर असमान

उड़ान और धोनी आउटफील्ड

